

‘सिंधु जल समझौते से बचने वाला पानी बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ व चूरु को मिलेगा’

मुख्यमंत्री भजनलाल ने गुसाईंसर बड़ा में अंत्योदय के शिविर का अवलोकन किया

बीकानेर, 8 जुलाई (कासं)। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान से रह हुए सिंधु जल समझौते से बचने वाला पानी बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरु को मिलने वाला है। ये चारों जिले बड़े सौभाग्यशाली हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने जो वादे किए हैं, वो सभी पूरे होंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस नेता आए तो पृष्ठना कि उनके वादों का क्या हुआ।

मुख्यमंत्री ने मंगलवार को बीकानेर के गुंसाईंसर बड़ा में पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़े के तहत आयोजित शिविर का अवलोकन करने के बाद आयोजित सभा को संबोधित किया। उनके साथ भाजपा के वरिष्ठ नेता राजेन्द्र राठौड़ भी थे।

■ **मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस ने सिर्फ घोषणा की, लेकिन हम श्री डूंगरगढ़ में ट्रॉमा सेंटर बनाने का काम करेंगे।**

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि श्रीडूंगरगढ़ के लिए जमीन देने का काम भी सरकार करेगी और इसके लिए जरूरी बजट भी दिया जायेगा। कांग्रेस ने जिस व्यापारी से घोषणा कराई थी, वो ये काम नहीं कर रहे हैं। कांग्रेस ने सिर्फ घोषणा की, लेकिन हम ट्रॉमा सेंटर बनाने का काम करेंगे। कांग्रेस ने व्यापारी पर दबाव बनाकर सिर्फ घोषणा करवा ली, अब वो टालमटोल कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का कहना है कि जब तक अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति का भला नहीं होगा, तब तक राजस्थान उत्कृष्ट नहीं होगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने इंदिरा गांधी नहर के लिए चार हजार



मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बीकानेर के गुंसाईंसर बड़ा में पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़े के तहत आयोजित शिविर का निरीक्षण किया और सभा को संबोधित किया।

करोड़ रूपए दिए हैं और बीकानेर, चूरु, श्रीगंगानगर में इससे काम होगा। किसान को पानी-बिजली और बीज देने का काम हमारी सरकार ने किया है।

विधायक ताराचंद सारस्वत ने अपने भाषण में मुख्यमंत्री के समक्ष

ट्रॉमा सेंटर बनाने की मांग रखी तथा सरकारी कॉलेज की घोषणा करने की मांग की।

ताराचंद सारस्वत के भाषण के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि आपके विधायक होशियार हैं। दो मिनट का बोला था,

लेकिन पूरे तीन पन्ने का भाषण बोल दिया।

उन्होंने अपनी सभी मांगें रख दी हैं। जो काम अधूरे हैं, उनके बारे में भी बोल दिया और जो करवाने हैं, उनके बारे में भी बोल दिया।

चिराग पासवान ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)
हत्याएं और अन्य अपराध बढ़ते जा रहे हैं। यह मेरे लिए भी चिंता का विषय है क्योंकि जिस सरकार का मैं समर्थन करता हूँ, वह सुशासन के लिए जानी जाती है।

चिराग तो अब विपक्षी नेताओं जैसी भाषा बोल रहे हैं। यह चौकाने वाला है। हालाँकि अभी तो चुनाव में समय है, देखना यह होगा कि चिराग नीतीश कुमार सरकार के खिलाफ अपनी बयानबाजी को कितना आगे ले जाते हैं। यह भी देखने की बात है कि क्या वे विधानसभा चुनाव लड़ने के लिये लोकसभा सांसद और केन्द्रीय मंत्री पद से वाकई इस्तीफा दे देंगे या फिर वे सीट बंटवारे में अच्छी डील हासिल कर के पीछे हट जाएँगे?

जो भी हो, एनडीए सहयोगियों के बीच सीट बंटवारे को लेकर आने वाले हफ्तों में तकरार तेज होने की पूरी संभावना है।

इज़रायल के प्र.मंत्री...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)
तनाव कम कराने तथा सर्बिया और कोसोवो के बीच समझौता कराने में उनके प्रयासों को अन्देखा किया। हालांकि भारत ने अधिकारिक रूप से पाकिस्तान के साथ हाल ही में हुए संघर्ष में ट्रंप की भूमिका का खंडन किया है और कहा है कि आपसी बातचीत से समाधान हुआ।

ट्रंप ने यह भी दावा किया है कि उन्होंने मिस्र, बर्मा और सूचना के बुलबुलों में बैटी महाशक्ति को संभालने के लिये जुझ रही है। इलेक्टोरल कॉलेज की विकृतियों, गैरिमांडरिंग (निर्वाचन क्षेत्रों की मनमानी रचना), और “विजेता ही सब कुछ ले जाए” व्यवस्था जनता में अलगाव और चरमपंथ को और बढ़ाती है।

अब अमेरिका की आगामी स्थिति क्या होगी। अब अमेरिका के सामने तीन संभावित रास्ते हैं: पहला है,

खुद को एक शांति निर्माता बताया था और वादा किया था कि वे अपने बातचीत के कौशल से यूक्रेन और गाज़ा के युद्धों को जल्दी खत्म करवा देंगे। लेकिन उनके राष्ट्रपति बनने के पांच महीने बाद भी ये दोनों संघर्ष जारी हैं।

नेतन्याहू और ट्रंप के बीच हुई बातचीत में गाज़ा में संघर्षविराम और बंधकों की रिहाई को लेकर एक समझौते पर काम करने पर चर्चा हुई। उसी दौरान, इज़राइल के अधिकारी कतर में हम्रास के साथ अप्रत्यक्ष वार्ता कर रहे थे, जिसमें अमेरिका मध्यस्थ की भूमिका निभा रहा था। ट्रंप ने बैटक से पहले ही अनुमान जताया था कि इस सप्ताह एक समझौता हो सकता है।

‘पुलवामा हमले के लिए विस्फोटक एमेज़ॉन से खरीदे गए थे’

आतंकी वित्तपोषण की वैश्विक निगरानी संस्था एफएटीएफ ने दावा किया

नई दिल्ली, 08 जुलाई। वैश्विक आतंकी वित्तपोषण निगरानी संस्था एफएटीएफ ने दावा किया है कि फरवरी 2019 के पुलवामा आतंकी हमले में इस्तेमाल किए गए विस्फोटक अमेजन से खरीदे गये थे। एफएटीएफ ने दावा किया कि 2022 में गोरखनाथ मंदिर पर हमला करने वाले आतंकी को पेमेंट पेपल से हुआ था। अप्रैल 2025 में पहलगाम में हुए आतंकी हमले की निंदा करते हुए एफएटीएफ ने कहा कि वित्तीय सहायता के बिना ऐसे हमले संभव नहीं थे। एफएटीएफ ने कहा था कि वह 200 अधिकार क्षेत्रों वाले अपने वैश्विक नेटवर्क द्वारा प्रदान किए गए मामलों

को संकलित करते हुए, आतंकवादी विरोधपोषण का व्यापक विश्लेषण करेगा। भारत में आतंकवादी हमले के लिए सामग्री की खरीद के लिए ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के उपयोग की केस स्टडी देते हुए, एफएटीएफ ने कहा कि हमले में इस्तेमाल किए गए तात्कालिक विस्फोटक उपकरण का एक प्रमुख घटक – एल्यूमीनियम पाउडर – ईपीओम अमेजन से खरीदा गया था। इस सामग्री का उपयोग विस्फोट के प्रभाव को बढ़

बिहार में 47 प्रतिशत मतदाताओं ने गणना फॉर्म जमा करवाए

नयी दिल्ली, 08 जुलाई। बिहार में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया में दो सप्ताह के अंदर चुनाव अधिकारियों को लगभग आधे मतदाताओं (47 प्रतिशत) के भरे हुए गणना-फार्म प्राप्त हो चुके हैं। यह जानकारी मंगलवार को आयोग द्वारा जारी एक विज्ञप्त में दी गयी। गणना-फार्म प्राप्त करने की अंतिम तिथि 25 जुलाई है। आयोग ने कहा है कि बिहार में पुनरीक्षण प्रक्रिया के तहत 3,70,77,077 गणना फार्म मिल चुके हैं, जो राज्य में कुल 7,89,69,844 मतदाताओं की संख्या का 46.95 प्रतिशत हैं। आयोग ने पुनरीक्षण के लिए दिशानिर्देश गत 24 जून को जारी किए थे। आयोग ने पुनरीक्षण के काम के लिए इन दो सप्ताह में 7.90 करोड़ फॉर्म मुद्रित कराए हैं और सूची में दर्ज 97 प्रतिशत से अधिक मतदाताओं (7,70,44,990) के गणना-फार्म वितरित किए जा चुके हैं। आयोग का कहना है कि अब तक 18.16 प्रतिशत फॉर्म उसके ऐप ईसीआईनेट पर अपलोड किए जा चुके हैं।

यह कदम ऐसे समय उठाया गया है, जब वाइट हाउस द्वारा शुरू किए गए कुछ सबसे आक्रामक आयात करों पर 90-दिवसीय रोक इस सप्ताह समाप्त होने वाली थी। ट्रंप ने जिन 14 देशों के नेताओं को औपचारिक पत्र भेजे हैं, उनमें सहयोगी और छोटे देश भी शामिल हैं। यह पत्र इस साल एक अगस्त को लागू होने वाले टैरिफ के बारे में हैं, जो ट्रंप की संरक्षणवादी नीतियों को दर्शाता है। पत्र में ट्रंप ने जापान और दक्षिण कोरिया से आयात पर 25 प्रतिशत टैरिफ लगाने की अपनी धमकी दोहराई और एक अगस्त से शुरू होने वाले संभावित शुल्कों के बारे में अन्य विश्व नेताओं को सूचित किया। उच्च टैरिफ शुरू में नौ जुलाई से प्रभावी होने वाले लेकिन अधिकारियों द्वारा नए व्यापार सौदों पर बातचीत करने की मांग के

अश्वनी पंजाब ...
(प्रथम पृष्ठ का शेष)
वहीं, अब भाजपा के संगठनात्मक ढाँचे को देखते हुए अश्वनी शर्मा को कार्यकारी अध्यक्ष बनाना रणनीतिक फैसला माना जा रहा है।

कांग्रेस ने माना कर्नाटक में पार्टी में अन्तर्कलह है

■ **कांग्रेस महासचिव सुरजेवाला ने कहा, कई विधायकों को पार्टी के प्रदेश नेतृत्व से शिकायत है।**
■ **लेकिन सुरजेवाला ने नेतृत्व परिवर्तन से इन्कार किया व कहा कि इस पर फैसला हाईकमान ही ले सकती हैं।**

बेंगलुरु, 08 जुलाई। कर्नाटक में किसी प्रकार की राजनीतिक अस्थिरता की सम्भावना को खारिज करते हुए कांग्रेस महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला ने मंगलवार को कहा कि राज्य में पार्टी के कई विधायकों को कुछ शिकायतें हैं और उनसे अपनी बात लिखकर देने को कहा गया है।

सुरजेवाला ने कहा कि वे विधायकों की समस्याओं को एक एक करके हल करेंगे। नाराज विधायकों, बीआर पाटिल और राजू कागे ने कई मसले उठाए हैं। कांग्रेस नेता ने यूनोवार्ता के एक सवाल पर कहा, कई विधायकों के पास मुझे और शिकायतें हो सकती हैं। मैंने उनसे कहा है कि वे सब मुझे लिखित में दें। हम उनका बारी बारी से हल निकालेंगे। कांग्रेस नेतृत्व का दावा है कि राज्य में पार्टी में हालात का दबाव में हैं लेकिन आम चर्चा यह है कि शिकायतों के सामने आने से पार्टी की अंदरूनी कलह दिखने लगी है। अब सुरजेवाला ने जो रुख अपनाया है, वह बंद कमरे में बातचीत

ट्रंप ने 14 देशों के लिए नए टैरिफ घोषित किए

ट्रंप ने इन सभी 14 देशों के राष्ट्र प्रमुखों को पत्र भेजकर सूचित कर दिया है

वाशिंगटन, 08 जुलाई। वैश्विक व्यापार में तनाव बढ़ाने वाले नए कदम में अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने बंगलादेश और म्यांमार सहित 14 देशों पर नए टैरिफ की घोषणा की है।

यह कदम ऐसे समय उठाया गया है, जब वाइट हाउस द्वारा शुरू किए गए कुछ सबसे आक्रामक आयात करों पर 90-दिवसीय रोक इस सप्ताह समाप्त होने वाली थी। ट्रंप ने जिन 14 देशों के नेताओं को औपचारिक पत्र भेजे हैं, उनमें सहयोगी और छोटे देश भी शामिल हैं। यह पत्र इस साल एक अगस्त को लागू होने वाले टैरिफ के बारे में हैं, जो ट्रंप की संरक्षणवादी नीतियों को दर्शाता है। पत्र में ट्रंप ने जापान और दक्षिण कोरिया से आयात पर 25 प्रतिशत टैरिफ लगाने की अपनी धमकी दोहराई और एक अगस्त से शुरू होने वाले संभावित शुल्कों के बारे में अन्य विश्व नेताओं को सूचित किया। उच्च टैरिफ शुरू में नौ जुलाई से प्रभावी होने वाले लेकिन अधिकारियों द्वारा नए व्यापार सौदों पर बातचीत करने की मांग के

■ **इन देशों में जापान व दक्षिण कोरिया जैसे बड़े देशों के अलावा म्यांमार, बांग्लादेश जैसे छोटे देश भी शामिल हैं। कई देश तो ऐसे हैं जो लम्बे समय से अमेरिका के सहयोगी रहे हैं।**

कारण इन्हें निलंबित कर दिया गया था। ट्रंप ने 'दृढ़ सोशल प्लेटफॉर्म' पर जापान और दक्षिण कोरिया को लिखे पत्र में कहा, यदि किसी कारण से आप अपने टैरिफ बढ़ाने का फैसला करते हैं, तो आप उन्हें जिस भी संख्या में बढ़ाना चाहते हैं, वह हमारे द्वारा लगाए जाने वाले 25 प्रतिशत में जोड़ दिया जाएगा। गौरतलब है कि उच्च टैरिफ एक अगस्त से प्रभावी होंगे और विशेष रूप से ऑटोमोबाइल, स्टील और एल्यूमीनियम जैसे पहले से घोषित सेक्टर टैरिफ के साथ नहीं जुड़ेंगे।

ट्रंप के पत्रों में जापान और दक्षिण कोरिया को चेतावनी दी गई थी कि उनके टैरिफ में किसी भी वृद्धि के साथ ही अमेरिकी शुल्कों में भी वृद्धि होगी। ट्रंप ने घोषणा की कि इसी तरह के पत्र

12 अन्य देशों के नेताओं को भेजे गए, जिनमें मलेशिया, कजाकिस्तान, दक्षिण अफ्रीका, म्यांमार, लाओस, टय्यूनीशिया, इंडोनेशिया, बंगलादेश, सर्बिया, बोत्सिया और हर्जेगोविना, कंबोडिया, थाईलैंड शामिल हैं। उन्हें यह सूचना दी गई कि अगले महीने से उन पर 25 प्रतिशत से 40 प्रतिशत तक टैरिफ लगाए जाएंगे। मलेशिया, कजाकिस्तान और ट्यूनीशिया पर टैरिफ दर 25 प्रतिशत होगी, जबकि दक्षिण अफ्रीका और बिर्हाना के लिए यह 30 प्रतिशत होगी। इंडोनेशिया पर 32 प्रतिशत और बांग्लादेश एवं सर्बिया पर 35 प्रतिशत टैरिफ दर लागू होगी। कंबोडिया और थाईलैंड पर टैरिफ दर 36 प्रतिशत होगी, जबकि लाओस एवं म्यांमार पर यह 40 प्रतिशत तक होगी।

और मीडिया की निगाहों से दूर रहने का प्रयास है। उन्होंने समस्या के हल के लिए कोई समय सीमा तय नहीं की है, जिससे लगता है कि पार्टी शिकायतों के निपटारे के मामले में कोई गंभीर कदम उठाने वाली नहीं है। राज्य में नेतृत्व बदलाव को लेकर उठे सवालों को दरकिनार करते हुए, उन्होंने एक मिसाल देते हुए कहा, एक

पत्रकार की संपादक बनने की आकांक्षा हो सकती है, लेकिन इस फैसले की डोर तो चैनल मालिक के हाथ में होती है। सुरजेवाला के बयान नेतृत्व संबंधी फैसलों पर कांग्रेस हाईकमान की मजबूत पकड़ को दिखाते हैं। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उपमुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार के दिल्ली दौरे के बारे में पूछे जाने पर, सुरजेवाला ने स्पष्ट किया कि वे दौरे पूरी तरह से प्रशासनिक हैं। उन्होंने कहा, "वे सरकारी काम से दिल्ली जा रहे हैं-ताकि वे केन्द्र के समक्ष कर्नाटक के मसले रख सकें। यह उनका कर्तव्य है और वे इसे पूरा कर रहे हैं।"

आज होगी

आपत्तिजनक दृश्य भी दिखाए गए हैं, जिनमें मुस्लिम मौलवियों को नाबालिग बच्चों के साथ समलैंगिक संबंध बनाते हुए दिखाया गया है।

इसी कारण, याचिकाकर्ता ने अदालत से मांग की है कि फिल्म और उसके ट्रेलर के रिलीज, प्रसारण, वितरण और सार्वजनिक प्रदर्शन पर रोक लगाई जाए। याचिका में यह भी अनुरोध किया गया है कि सूचना और प्रसारण मंत्रालय को निर्देश दिए जाए कि वह इस फिल्म के ट्रेलर को यूट्यूब, फेसबुक और व्हाट्स (पूर्व में ट्विटर) जैसे सभी डिजिटल और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से तुरंत हटवाए। फिल्म के निर्देशक और निर्माता के अलावा, याचिका में डिस्ट्रीब्यूटर रिलार्यंस एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड, गूगल, एक्स और मेटा को भी पार्टी बनाया गया है।

रेल मंत्री अश्विनी ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)
वैष्णव समाज में परम्परा रही है कि घर के किसी वयोवृद्ध सदस्य का निधन होता है, तो बैकुंठी निकाली जाती है। अंतिम संस्कार भी पार्थिव देह को बैठाकर ही किया जाता है। रेल मंत्री बनने के बाद 2 अक्टूबर 2021 को पहली बार अश्विनी वैष्णव जोधपुर आए थे। इस दौरान पिता-पुत्र की मुलाकात काफी कम समय के लिए हो पाई थी, तब दाऊलाल वैष्णव ने अश्विनी वैष्णव को एक चिट्ठी लिखी।

उन्होंने लिखा- कर्तव्य को इतनी निष्ठा से निष्पादित करो कि हर रेलयात्री का चेहरा यात्रा के दौरान फूल सा खिले।

स्व. दाऊलाल वैष्णव की अंतिम यात्रा में भारतीय जनता पार्टी के अनेक नेताओं सहित, शहर के लोग उपस्थित थे। अंतिम संस्कार के काग मशान घाट पर सीएम भजनलाल शर्मा तथा भाजपा नेता राजेन्द्र राठौड़ भी पहुंचे।

एसआई भर्ती ...

पूर्ववर्ती रिपोर्ट को किस तरह प्राप्त किया गया? यदि याचिकाकर्ता ने अनाधिकृत तरीके से यह रिपोर्ट हासिल की है तो भी याचिका को खारिज किया जाना चाहिए। महाधिवक्ता की ओर से यह भी कहा गया कि याचिकाकर्ता भर्ती प्रक्रिया में शामिल हुए, लेकिन फेल होने पर लंबे समय बाद हाईकोर्ट आ गए। दूसरी ओर अदालत ने कहा कि सरकार याचिका को कभी प्री-मैच्योर बता रही है तो कभी उसे सारहीन बताकर खारिज करने की गृहार की रही है। इसके साथ ही अदालत ने मामले को सुनवाई बुधवार तक टालते हुए, राज्य सरकार को प्रकरण से जुड़ा रिकॉर्ड साथ लाने को कहा है।